ब्रिक्स देशों में बढ़ा भारत का निर्यात

- चार प्रमुख ब्रिक्स देशों को निर्यात 34% बढ़ा
- जापान, इटली और दक्षिण कोरिया में भी तेजी

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

नयी दिल्ली, 21 सितंबर चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच माह (अप्रैल-अगस्त) के दौरान चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस को भारत का निर्यात 34 प्रतिशत बढ़कर 19.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया.

इस वृद्धि में चीन को भेजे जाने वाले सामान में 39 प्रतिशत 19.6 अरब डॉलर की तेजी का मुख्य रूप से योगदान रहा. इससे भारत के निर्यात विस्तार के लिए ब्रिक्स समूह के बढ़ते महत्व का पता चलता है. एक अधिकारी ने कहा कि भारत जैसे-जैसे ब्रिक्स समूह के साथ अपनी भागीदारी गहरी कर रहा है, सबसे मजबूत रफ्तार इसके संस्थापक सदस्यों चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस की ओर से देखने को मिल रही है.

देश/क्षेत्र	अवधि 2026-27 (अप्रैल-अगस्त)	वृद्धि
चीन	$9.6 अरब	39%
दक्षिण अफ्रीका	—	58%
ब्राजील	—	13%
रूस	—	11%
चार ब्रिक्स देश	$19.9 अरब	34%
जापान	$3.43 अरब	43%
इटली	$3.92 अरब	30%
दक्षिण कोरिया	$3.21 अरब	22%

ब्रिक्स के 4 देशों को एक्सपोर्ट बढ़ा

- मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बने ब्रिक्स का विस्तार 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को शामिल करके किया गया था, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ.
- बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाइलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम पिछले साल ब्रिक्स के भागीदार देश बने, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन 4 प्रमुख ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं को होने वाला निर्यात 34 प्रतिशत बढ़ा है, जो अप्रैल-अगस्त, 2025-26 के 14.9 अरब डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अगस्त, 2026-27 में 19.9 अरब डॉलर हो गया.
- भारत के कुल निर्यात में इन चार देशों की हिस्सेदारी चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गई, जो 2025-26 की समान अवधि में 8.1 प्रतिशत थी प्रमुख ब्रिक्स देशों में चीन सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा.
- वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में चीन को भारतीय निर्यात 39 प्रतिशत बढ़कर 9.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया, दक्षिण अफ्रीका के मामले में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई और इस अवधि में वहां होने वाला निर्यात 58 प्रतिशत बढ़ा.

दुनिया की नजर भारत पर, प्रतिस्पर्धा जरूरी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नयी दिल्ली, 21 सितंबर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पर भी व्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है. यस बैंक की एक शोध - रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच व्याज दरों का अंतर और कम हुआ है. ऐसे में अक्टूबर में आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है.

हालांकि, आरबीआई का फैसला घरेलू आर्थिक विकास और महंगाई की स्थिति पर निर्भर करेगा. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती बनी हुई है. अगस्त में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई बढ़ी है. मुख्य महंगाई यानी कोर इंफ्लेशन में भी बढ़ोतरी हुई है.

टाटा विवाद में कानूनी खर्च पर रोक

- टीईडीटी ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने जताई आपत्ति
- ट्रस्ट फंड से खर्च की आशंका पर सवाल
- टाटा संस में ट्रस्ट्स की 66% हिस्सेदारी अहम

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नयी दिल्ली, 21 सितंबर टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (टीईडीटी) के ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने साफ कर दिया है कि ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बोर्ड के बीच एन चंद्रशेखरन की दोबारा को नियुक्ति लेकर चल रहे विवाद से जुड़े किसी भी कानूनी खर्च का भुगतान नहीं करेगा.

टीईडीटी के कोष का अनुमान करीब 5,000 करोड़ रुपये बताया गया है. मेहली ने टाटा ट्रस्ट्स के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को ईमेल भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. इसकी प्रति टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल एन टाटा और टीईडीटी के दूसरे ट्रस्टी जेएन मिस्त्री को भी भेजी गई है. मेहली ने कहा कि ट्रस्टी, टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच चल रहा मुकदमा पिछले 150 वर्षों में अभूतपूर्व है. उन्होंने विवाद में शामिल लोगों के अनुभव या रवैये पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए टीईडीटी के रुख को स्पष्ट किया. उनका कहना है कि टीईडीटी टाटा संस का शेयरधारक नहीं है और इसलिए इन विवादों से अलग है.

मेहली मिस्त्री के ईमेल में यह नहीं कहा गया है कि टीईडीटी का पैसा फिलहाल इस विवाद से जुड़े कानूनी खर्च में इस्तेमाल किया जा रहा है. ईमेल में ऐसा भी नहीं कहा गया है कि इस तरह के खर्च का कोई प्रस्ताव सामने आया है. उनकी आपत्ति इस आशंका पर आधारित है कि टीईडीटी से भविष्य में ऐसे कानूनी खर्च उठाने को कहा जा सकता है.

रतन टाटा ट्रस्ट के पास 23.56 फीसदी हिस्सेदारी

मेहली ने मांग की है कि उनका ईमेल 20 नवंबर 2026 को होने वाली टीईडीटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली बैठक में रखा जाए और रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को टाटा संस बोर्ड को बताया था कि वह मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए अपना नाम पेश नहीं करेंगे. इसके बाद सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) ने उनके फैसले का सम्मान करते हुए नए चेयरमैन के चयन के लिए चयन समिति बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया. लेकिन 17 सितंबर को टाटा संस बोर्ड ने 4:1 के मतदान से चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी. नोएल टाटा ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया. विवाद में टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में बहुमत हिस्सेदारी भी अहम है. टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी इक्विटी शेयर पूंजी है. 2 प्रमुख ट्रस्टों में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के पास 27.98 फीसदी और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास 23.56 फीसदी हिस्सेदारी है. दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 51.54 फीसदी है.

फेड के फैसले से आरबीआई पर दबाव

- अक्टूबर में रेपो रेट बढ़ने की संभावना
- भारत-अमेरिका ब्याज अंतर हुआ कम

नयी दिल्ली, 21 सितंबर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पर भी व्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है.

यस बैंक की एक शोध - रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच व्याज दरों का अंतर और कम हुआ है. ऐसे में अक्टूबर में आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है. हालांकि, आरबीआई का फैसला घरेलू आर्थिक विकास और महंगाई की स्थिति पर निर्भर करेगा.

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती बनी हुई है. अगस्त में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई बढ़ी है. मुख्य महंगाई यानी कोर इंफ्लेशन में भी बढ़ोतरी हुई है.

एनएसई आईपीओ को 1.75 गुना सब्सक्रिप्शन

जीएमपी घटकर 59 पर आया, 3.31% संभावित लिस्टिंग गेन; 22 सितंबर को अलॉटमेंट संभव

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

नई दिल्ली, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को अंतिम दिन निवेशकों की ओर से 1.75 गुना अभिदान मिला. 22,569 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में 8,86,42,911 शेयरों के मुकाबले 12,89,85,128 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं.

निवेशकों की श्रेणी में सबसे ज्यादा मांग गैर-संस्थागत निवेशकों की रही, जिनका हिस्सा 2.89 गुना अभिदान हुआ. इसके बाद पात्र संस्थागत खरीदारों का हिस्सा 2.29 गुना भरा. खुदरा निवेशकों की ओर से 95 प्रतिशत अभिदान मिला.आईपीओ की चर्चा के बीच ग्रे मार्केट में एनएसई

के शेयर का प्रीमियम भी कमजोर हुआ है. इनवेस्टग्रेन के आंकड़ों के अनुसार 21 सितंबर की सुबह 11:30 बजे तक ग्रे मार्केट प्रीमियम) 59 रुपये था. कंपनी ने आईपीओ के लिए 1,700 से 1,785 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है. ऊपरी मूल्य दायरे के आधार पर 59 रुपये के जीएमपी से अनुमानित लिस्टिंग कीमत करीब 1,844 रुपये बनती है. यानी इश्यू मूल्य की तुलना में करीब 3.31 प्रतिशत संभावित लिस्टिंग प्रीमियम का संकेत मिलता है. हालांकि, जीएमपी अनौपचारिक संकेतक है और इससे वास्तविक लिस्टिंग कीमत या निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की गारंटी नहीं होती.

एनएसई के आईपीओ में मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 12.64 करोड़ इक्विटी शेयरों की पूरी तरह बिक्री पेशकश शामिल है. इसलिए इस आईपीओ से एनएसई को सीधे कोई रकम नहीं मिलेगी. शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि, इश्यू से जुड़े खर्चों को छोड़कर, बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी. कंपनी का लक्षित मूल्यांकन करीब 4.42 लाख करोड़ रुपये है.

आईपीओ से पहले 16 सितंबर को एनएसई ने कई बड़े घरेलू और वैश्विक निवेशकों से 6,746.2 करोड़ रुपये जुटाए थे. इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे बड़ा निवेशक रहा. एंकरचेंज ने ऊपरी मूल्य दायरे पर 189 एंकर निवेशकों को 3.77 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं.कर्मचारियों के लिए 70 करोड़ रुपये के शेयर आरक्षित रखे गए हैं. इन्हें अंतिम निर्गम मूल्य से 170 रुपये प्रति शेयर की छूट पर देने का प्रावधान है. शेयरों का आवंटन 22 सितंबर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जबकि एनएसई के शेयर 24 सितंबर से बीएसई पर कारोबार के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

लंबित मामलों के निपटारे और स्वच्छता पर जोर

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 21 सितंबर. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6.0 चलाने की तैयारी में है. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के तहत आयोजित होने वाले इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाना है.

इस बार अभियान में ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही जनता से

सीधे जुड़े क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों को भी अभियान में शामिल किया जाएगा. अभियान का तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर तक चल रहा है. इस दौरान मंत्रालय कार्यालयों से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कर्मचारियों को अभियान के प्रति जागरूक कर रहा है और कार्ययोजना तैयार की जा रही है. 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले मुख्य चरण में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान, कामकाज के डिजिटलीकरण, अभिलेखों की छंटाई, कार्यालयों में स्थान प्रबंधन और लंबित सांसद संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों तथा लोक शिकायतों के निपटारे पर काम किया जाएगा.

विशेष अभियान 5.0 के दौरान मंत्रालय और उसके विभिन्न संगठनों ने 23,162 भौतिक फाइलों की समीक्षा की. इनमें से 4,280 फाइलों की छंटाई की गई.

22,365 लोक शिकायतों का निपटारा

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निर्देशों के बाद नवंबर 2025 से सितंबर 2026 तक अभियान की गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया. इस दौरान मंत्रालय और उसके संगठनों ने 22,365 लोक शिकायतों, 4,850 लोक शिकायत अपीलों और 226 सांसद संदर्भों का निपटारा किया. समीक्षा के बाद 626 भौतिक और 127 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की छंटाई की गई तथा करीब 1,167 वर्गफुट कार्यालयी जगह खाली कराई गई मंत्रालय के अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालयों और संस्थानों का दौरा कर कर्मचारियों को अभियान के प्रति जागरूक किया और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी की.

गोबर से गांवों में खुलेंगे कमाई के रास्ते

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नयी दिल्ली, 21 सितंबर सरकार ने 23,731 करोड़ रुपये की 'गोबरधन' योजना को लागू कर दिया है. इस योजना के तहत तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को उनकी बिक्री योग्य गैस की 100 प्रतिशत तक सुनिश्चित खरीद, कम से कम 10 साल के लिए प्रशासित मूल्य और पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जारी परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी.

एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार जरूरी

- 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य
- 27.43 करोड़ उपभोक्ता करा चुके सत्यापन

नवभारत न्यूज नेटवर्क.

नयी दिल्ली, 21 सितंबर घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सब्सिडी के साथ तय खुदरा कीमत पर घरेलू एलपीजी रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा.

सरकार के मुताबिक, 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं. यह कुल सक्रिय उपभोक्ताओं का 89.9 प्रतिशत है. जिन लोगों ने प्रमाणीकरण करा लिया है, उन्हें अब कोई अतिरिक्त कार्यवाही नहीं करनी होगी और उन्हें पहले की तरह एलपीजी रिफिल मिलता रहेगा. 1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी रिफिल की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा. आधार प्रमाणीकरण रिफिल की डिलीवरी के समय, एलपीजी वितरक के शोरूम या तीनों सरकारी तेल कंपनियों के मोबाइल एप के जरिए किया जा सकता है.

इंडेन उपभोक्ता इंडियन ऑयल वन एप, भारत गैस उपभोक्ता हेलोबीपीसीएल और एचपी गैस उपभोक्ता एचपी पे के जरिए घर बैठे प्रमाणीकरण कर सकते हैं.

समाचार विशेष

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे पंजाब

'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' में हुए शामिल, विशाल जनसभा को किया संबोधित

बठिंडा/नई दिल्ली, 21 सितंबर 2026 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को पंजाब दौरे पर रहे. शिवराज सिंह ने यहां तख्त श्री दमदमा साहिब गुरूद्वारे में मत्था टेका, वहीं उन्होंने तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी में भारतीय जनता पार्टी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' का शुभारंभ किया और यात्रा में शामिल भी हुए, शिवराज सिंह ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहली बार दमदमा साहिब आने का अवसर मिला, लेकिन यहां नशे से प्रभावित परिवारों की पीड़ा देखकर मेरा मन व्यथित है. उन्होंने कहा कि नशे के कारण कई परिवारों ने अपने बेटे खो दिए हैं, कई बहनों की गोद सूनी हो गई है और कई परिवारों के सामने जीवन का सहारा छिन गया है. शिवराज सिंह ने कहा कि मैंने उन बहनों से मुलाकात की, जिनके बेटे नशे के कारण असमय दुनिया से चले गए. किसी का बेटा 18 साल का था, किसी का 21 साल का, किसी का 27 साल का और एक बहन के पति की उम्र केवल 31 वर्ष थी. उन्होंने कहा कि कई पिता अपनी बुढ़ापे की लाठी खो चुके हैं और कई बहनों की मांग का सिंदूर नशे के कारण उजड़ गया है. साथ ही, केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब ये बहनें अपनी व्यथा सुना रही थीं, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका कलेजा कांप रहा था.

आप का अलायंस कांग्रेस के लिए खतरा

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी की राजनीति का एक हिस्सा अपने चुनाव जीतने का तो है लेकिन साथ ही दूसरा हिस्सा कांग्रेस को कमजोर करते जाने का भी है. पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गोवा और गुजरात में कांग्रेस का बड़ा नुकसान किया था.

गुजरात में आप को 13 फीसदी के करीब वोट मिले थे, जिसकी वजह से कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई थी. आप के पांच विधायक जीते थे. पहली बार हुआ कि गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई.

इसी तरह गोवा में आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने मिल कर कांग्रेस की संभावनाओं को मटियामेट कर दिया. ध्यान रहे 2017 के चुनाव में कांग्रेस 17 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी थी. लेकिन 2022 में आप और तृणमूल ने मिल कर करीब 12 फीसदी वोट हासिल किए, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ. आप के दो सीटें मिली थीं. अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर गोवा में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है.

नतीजों से नंदीग्राम तक बदले सुर

सियासी गणित के बीच विपक्षी एकता की नई जमीन तैयार

नई दिल्ली. ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक दूरी कम होने के संकेत अब जमीन पर भी दिख रहे हैं. हालांकि इसकी शुरुआत अभी के घटनाक्रम से नहीं हुई. बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद ममता के रुख में कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ संवाद को लेकर नरमी दिखाई दी थी.

अब चुनाव आयोग के आदेश के बाद पैदा हुए विवाद और राहुल गांधी से बातचीत के बाद यह संवाद समर्थन तक पहुंचा है. गुरुवार रात राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बात की. बातचीत चुनाव आयोग के आदेश से पैदा हुई स्थिति को लेकर हुई. राहुल ने ममता को जरूरत पडने पर हर संभव मदद का भरोसा दिया. ममता ने इसके बाद कहा कि हम इसमें साथ हैं. हम भाजपा को हटाना चाहते हैं.

उन्होंने बंगाल को एकजुट इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता दिखाने वाला राज्य बनाने की बात भी कही.

इसके अगले दिन ममता ने नंदीग्राम में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया. असम में भी कांग्रेस के साथ खड़े होने की घोषणा की गई. इस तरह बातचीत का असर एक चुनावी सीट पर सीधे राजनीतिक समर्थन के रूप में सामने आया. 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 294 में 207 सीटें जीतीं, जबकि टीएमसी को 80 सीटें मिलीं. 2021 में टीएमसी ने 213 और भाजपा ने 77 सीटें जीती थीं. इन नतीजों के बाद बंगाल की राजनीति में सत्ता का समीकरण बदला. इसी अवधि में ममता का विपक्षी दलों के साथ संपर्क बढ़ना और कांग्रेस के साथ संवाद को लेकर उनका रुख नरम होना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा.

चुनाव आयोग विवाद बना साझा मुद्दा

टीएमसी भीतर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग के आदेश से पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर अलग व्यवस्था बनी. इसी घटनाक्रम के बीच राहुल और ममता की बातचीत हुई. दोनों नेताओं की बातचीत ने लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक दूरी के बीच साझा मुद्दे पर संवाद का रास्ता खोला. इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद टीएमसी और कांग्रेस बंगाल में लंबे समय से अलग-अलग राजनीतिक रास्ते पर रहे हैं. यही स्थिति विपक्षी एकता के सामने राज्य स्तर पर समन्वय की चुनौती को दिखाती रही है. इन ताजा घटनाक्रमों से फिलहाल टीएमसी और कांग्रेस के बीच मुद्दा-आधारित राजनीतिक समन्वय सामने आया है. नंदीग्राम और असम में समर्थन के फैसले के बाद दोनों दलों के बीच यह तालमेल आगे किन मुद्दों और किन राज्यों तक बढ़ता है, यह उनके अगले राजनीतिक कदमों से स्पष्ट होगा.

विशेष | चक्रव्यूह भेदने बीजेपी की रणनीति, ढाई साल में सरकार का लिटमस टेस्ट

कांग्रेस शासित निगमों में चुनाव

रायपुर. छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की आहट के साथ ही प्रदेश के चार बड़े नगर निगमों की सियासत गरमा गई है. भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बिरगांव, चारों नगर निगम फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में हैं.

लेकिन प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा अब इन शहरी किलों में सेंध लगाने की तैयारी में जुट गई है.

बीजेपी ने प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनावी चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है, तो कांग्रेस भी अपने कब्जे वाले निगमों को बचाने के लिए संगठन को सक्रिय कर रही है. मुकाबला सिर्फ चार नगर निगमों की सत्ता का नहीं है. भिलाई-चरौदा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रभाव की परीक्षा होगी, तो रिसाली में पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की राजनीतिक पकड़ भी कसौटी पर होगी. यही वजह है कि इन निकाय चुनावों को स्थानीय सरकार के चुनाव से कहीं आगे, कांग्रेस और भाजपा के बीच शहरी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है.

आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बिरगांव सबसे अहम राजनीतिक केंद्र बनकर सामने आए हैं. चारों नगर निगमों में फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है. ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मौजूदा राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय संगठन को बचाए रखने की है. दूसरी तरफ प्रदेश की सत्ता भाजपा के पास है.भाजपा की कोशिश है कि राज्य सरकार के कामकाज, संगठन की ताकत और स्थानीय स्तर पर मजबूत उम्मीदवारों के जरिए कांग्रेस के इन शहरी गढ़ों में सेंध लगाई जाए. महापौर पद के साथ-साथ पार्षदों की अधिक से अधिक सीटें हासिल करना भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा है. यानी इस चुनाव में एक तरफ कांग्रेस की स्थानीय पकड़ है, तो दूसरी तरफ भाजपा के पास सत्ता और संगठन की ताकत. यही समीकरण इन चारों नगर निगमों के चुनाव को दिलचस्प बना रहा है.

भूपेश बघेल के प्रभाव की अग्निपरीक्षा- चारों नगर निगमों में भिलाई-चरौदा का चुनाव राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है. यह इलाका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रभाव क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है.

भाजपा ने तैयार किया चुनावी चक्रव्यूह

भाजपा ने चुनावी तैयारियों में संगठन को मैदान में उतार दिया है. चारों नगर निगमों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. बिरगांव की जिम्मेदारी सौरभ सिंह को प्रभारी के तौर पर दी गई है, जबकि भावना बोहरा और कमल गर्ग सह-प्रभारी होंगे .भिलाई नगर निगम की जिम्मेदारी भूपेंद्र सवन्नी को दी गई है, जबकि लक्ष्मी वर्मा और चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी सह-प्रभारी होंगे. रिसाली में अनुराग सिंहदेव प्रभारी होंगे और श्वेता शर्मा और आसू चंद्रवंशी सह-प्रभारी की भूमिका निभाएंगे.